



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 7, 2002/पौष 17, 1923

No. 2]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 7, 2002/PAUSA 17, 1923

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2002

सं. टीएएमपी/119/2001-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963(1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार अपनी दरों के मान में पाइन वुड के प्रहस्तन के लिए क्रेन प्रभारों की दर शामिल करने के चेन्नई पत्तन न्यास के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है।

आदेश

मामला सं. टीएएमपी/119/2001-सीएचपीटी

चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी)

आवेदक

(जनवरी, 2002 के प्रथम दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) में 'प्रति घन मीटर' आधार पर नरम लकड़ी के लट्ठों के लिए घाटशुल्क निर्धारित करने के बारे में M0 गुप्ता ग्लोबल एक्विजि प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन से संबंधित मामला सं. टीएएमपी/66/2001-सीएचपीटी में 5 नवंबर, 2001 को एक आदेश पारित किया था। इस प्राधिकरण ने तब पाइन वुड के लिए घाटशुल्क शामिल करने हेतु सीएचपीटी की दरों के मान में घाटशुल्क अनुसूची की मद 88 में संशोधन किया था। इस प्राधिकरण का दरों के मान में संशोधन करने से संबंधित आदेश 20 नवंबर, 2001 को राजपत्र सं. 300 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग-III खंड 4) में अधिसूचित किया गया था।

2. उपर्युक्त आदेश के संदर्भ में, सीएचपीटी ने अब अपनी दरों के मान में पाइन वुड के प्रहस्तन के लिए क्रेन प्रभारों को शामिल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सीएचपीटी ने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें कही हैं :-

(i) M0 गुप्ता ग्लोबल एक्विजि प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, इस प्राधिकरण ने इस बात को ध्यान में रखे

- बिना कि पाइन वुड किस रूप में आती है और अंततः यह किस प्रयोग में आती है, उसके लिए सीएचपीटी की दरों के मान में घाटशुल्क शामिल करते हुए संशोधन का आदेश पारित किया था।
- (ii) मै0 गुप्ता ग्लोबल एक्विजि प्राइवेट लिमिटेड के अभ्यावेदन पर 5 अक्तूबर, 2001 को हुई संयुक्त सुनवाई में केवल लकड़ी के लट्ठों, दियासलाई बनाने की लकड़ी और लकड़ी के अन्य रूपों पर वसूल किए जा रहे घाटशुल्क प्रभारों और न्यूजीलैंड से आयात किए जाने वाले नए कार्गो पाइन वुड के लट्ठों/लकड़ी पर वसूल किए जाने वाले घाटशुल्क के बारे में ही चर्चा हुई थी।
- (iii) इस प्राधिकरण ने नए कार्गो पाइन वुड के लट्ठों/लकड़ी के आयात के लिए दरों के मान में घाटशुल्क और क्रेन प्रभारों दोनों के संशोधन के लिए सीएचपीटी से प्रस्ताव प्राप्त होने से पहले ही अपना आदेश पारित कर दिया था।
- (iv) चूंकि लकड़ी के प्रहस्तन के लिए क्रेन प्रभार सीएचपीटी की दरों के मान में अलग से दिए गए हैं और जब भी पाइन वुड के लट्ठों/लकड़ी के लिए घाटशुल्क में संशोधन किया जाना हो तो दरों के मान में पाइन वुड के लट्ठों/लकड़ी के प्रहस्तन के लिए क्रेन प्रभारों में भी साथ-साथ संशोधन किया जाना चाहिए।
- (v) सीएचपीटी की दरों के मान की पुस्तिका-I, अध्याय-III, मान क-सामान्य की मद सं. 1 (ii) (ग) में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है :-

मद सं.	इस मान के प्रयोजन से वर्गीकरण	रुपए	पैसे	प्रभार
1 (ii) (ग)	पाइन वुड सहित लकड़ी, इस बात को ध्यान में रखे बिना कि यह किस रूप में आती है और अंततः यह किस प्रयोग में आती है, परंतु उपर्युक्त मद (ii) (क) और (ख) में यथा विनिर्दिष्ट अन्य लट्ठे शामिल नहीं हैं।	38	- 60	प्रति घन मीटर प्रति ऊंचाई

3. चूंकि सीएचपीटी ने लकड़ी के लिए क्रेन प्रभारों में किसी वृद्धि का प्रस्ताव नहीं किया है और पाइन वुड के लिए न्यूनतम वर्तमान क्रेन प्रभारों को अपनाने का प्रस्ताव किया है, इसलिए इस मामले में प्रयोक्ताओं से परामर्श करना आवश्यक नहीं समझा गया।

4. इस मामले में उपलब्ध समग्र सूचना के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है :-

- (i) सीएचपीटी लकड़ी यातायात पर घाटशुल्क और क्रेन प्रभार अलग-अलग वसूल करता है। लकड़ी के लिए लागू घाटशुल्क अनुसूची में अवशिष्ट प्रविष्टि में 'पाइन वुड' को शामिल करने के लिए पहले ही संशोधन कर दिया गया है। क्रेन प्रभार अनुसूची में भी अवशिष्ट प्रविष्टि शामिल है; और घाटशुल्क अनुसूची के अंतर्गत किए गए निर्धारण के अनुकूल इसे परिष्कृत करने का प्रस्ताव किया गया है।
- (ii) क्रेन प्रभारों में किसी वृद्धि का प्रस्ताव नहीं है। यह पाइन वुड के वर्तमान प्रभारों का न्यूनतम लागू करने का इच्छुक है। इसके अलावा, यह प्रस्ताव केवल दरों के मान में आंतरिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए किया गया है। ऐसी स्थिति में, यह प्राधिकरण सीएचपीटी के प्रस्ताव का अनुमोदन करना चाहता है।
- (iii) यह सच है कि घाटशुल्क अनुसूची में किए गए बदलाव के साथ क्रेन प्रभार में तदनुरूपी बदलाव किए जाने चाहिए थे। लकड़ी के लिए घाटशुल्क और क्रेन प्रभार अनुसूचियों के बीच अंतर्सम्बन्ध का उल्लेख करते हुए पूर्व कार्यवाही में न सीएचपीटी से और न ही प्रयोक्ताओं से परामर्श किया गया। हम स्वीकार करते हैं कि यह बात भी हमारे ध्यान में नहीं आ पाई थी।
- (iv) प्रशुल्क निर्धारण प्रक्रिया के बारे में सीएचपीटी की समझ सही नहीं है। इस प्राधिकरण को दरों के मान में कोई परिवर्तन करने के लिए किसी पत्तन न्यास के प्रस्ताव की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। पत्तन न्यासों के प्रस्तावों के बावजूद, यह प्राधिकरण अपनी ओर से निर्णय कर सकता है और प्रयोक्ताओं से प्राप्त अभ्यावेदन पर उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है। पाइन वुड पर घाटशुल्क के बारे में मै0 गुप्ता ग्लोबल एक्विजि प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर निर्णय लेने से पूर्व सीएचपीटी से परामर्श किया गया था। हालांकि अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद उसने कोई लिखित निवेदन नहीं किया था, परंतु सीएचपीटी ने उस मामले में की गई संयुक्त सुनवाई में भाग लिया था। संयुक्त सुनवाई में सीएचपीटी ने यह नहीं बताया था कि वह एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। ऐसी स्थिति में, इस मामले का निर्णय उपलब्ध अभिलेखों और दी गई सूचना के आधार पर लिया गया था। यह ऐसी स्थिति में सीएचपीटी अपने प्रस्ताव के बिना मामले पर निर्णय लेने के बारे में आपत्ति नहीं कर सकता।

- (v) इस प्राधिकरण के 5 नवंबर, 2001 के आदेश द्वारा लकड़ी की घाटशुल्क अनुसूची में संशोधन किया गया था। यह आदेश 20 नवंबर, 2001 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और इसलिए यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी हो गया था। चूंकि मौजूदा प्रस्ताव प्रहस्तन प्रमारों के अन्य घटक की वसूली के लिए है और इसे दरों के मान में आंतरिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए अनुमोदित किया जा रहा है, इसलिए संबद्ध घाटशुल्क अनुसूची में संशोधन किए जाने की तारीख से पूर्व प्रमाण से सीएचपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित क्रेन प्रमार अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।
5. परिणामस्वरूप और उपर्युक्त कारणों से, यह प्राधिकरण सीएचपीटी की दरों के मान के मान क-सामान्य; अध्याय-III की मद सं. 1 (ii) (ग) - क्रेनों और फोर्क लिफ्ट ट्रकों के प्रमार में निम्नलिखित संशोधन करने का अनुमोदन करता है :-

मद सं.	इस मान के प्रयोजन से वर्गीकरण	रुपए पैसे	प्रमार
1 (ii) (ग)	पाइन वुड सहित लकड़ी, इस बात को ध्यान में रखे बिना कि यह किस रूप में आती है और अंततः यह किस प्रयोग में आती है, परंतु उपर्युक्त मद (ii) (क) और (ख) में यथा विनिर्दिष्ट अन्य लट्ठे शामिल नहीं हैं।	38 - 60	प्रति घन मीटर प्रति कंचाई

6. यह आदेश 20 नवंबर, 2001 से पूर्व प्रमाण से लागू होगा।

एस. सत्यम, अध्यक्ष
[विज्ञापन III/IV/143/2002/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2002

No. TAMP/119/2001-CHPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal of the Chennai Port Trust for inclusion of the rate of the crane charges for handling pine-wood in its Scale of Rates as in the Order appended hereto.

ORDER

Case No. TAMP/119/2001-CHPT

The Chennai Port Trust (CHPT)

- - -

Applicant

(Passed on this 1st day of January 2002)

This Authority had passed an Order on 5 November 2001 in case No. TAMP/66/2001-CHPT relating to a representation submitted by M/s. Gupta Global Exim Pvt. Limited about fixation of wharfage for soft timber logs on a 'per Cubic Meter' basis at the Chennai Port Trust (CHPT). This Authority then modified Item 88 of the Wharfage schedule in the Scale of Rates of the CHPT to include wharfage for pine-wood. The Order of this Authority modifying the Scale of Rates was notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 20 November 2001 vide Gazette No.300.

2. With reference to the above Order, the CHPT has now submitted a proposal for inclusion of crane charges for handling pine-wood in the Scale of Rates of the CHPT. In its proposal, the CHPT has made the following points:

- (i). On the basis of a representation received from M/s. Gupta Global Exim Pvt. Limited, the Authority passed an Order amending the Scale of Rates of the CHPT by including wharfage for pine wood irrespective of the form in which it comes and of its end use.

- (ii). In the joint hearing on the representation of M/s. Gupta Globle Exim Pvt. Limited held on 5 October 2001, it was discussed only about the wharfage charges being levied on the timber logs, match wood and timber in other forms and on the wharfage to be levied on the new cargo of pine logs / wood to be imported from New Zealand.
- (iii). The Authority passed its Order before receiving a proposal from the CHPT for amendment of both the wharfage and crane charges in the Scale of Rates for import of new cargo of pine logs/wood.
- (iv). Since the crane charges for handling the timber is separately provided in the Scale of Rates of the CHPT, and as when the wharfage, for pine logs / wood is amended, the crane charges for handling the pine logs / wood are also required to be amended simultaneously in the Scale of Rates.
- (v). It is proposed to amend Item No.1 (ii) (c) in Scale A-General, Chapter III, Book-I of the Scale of Rates of the CHPT as given below:

Item No.	Classification for purposes of this Scale	Rs. Ps.	Charge
1 (ii) (c)	Timber including pine-wood irrespective of the form in which it comes and of its endues but excluding other logs as specified in item ii (a) and (b) as above	38.60	Per Cubic metre per hoist

3. Since the CHPT has not proposed any increase in crane charges for timber and proposed to adopt the lowest of the existing crane charges for pine-wood, consultation with users was found not necessary in this case.

4. With reference to the totality of information available in this case, the following position emerges:

- (i). The CHPT levies wharfage and cranage separately on timber traffic. The residual entry in the wharfage schedule applicable for timber has already been modified to include 'pine-wood'. The cranage schedule also contains a residuary entry; and, the proposal is to elaborate it in tune with the prescription made under wharfage schedule.
- (ii). The proposal is not for any increase in cranage charges. It seeks application of the lowest of the existing charges for pine-wood. Further, this proposal is made only to bring internal consistency in the Scale of Rates. That being so, this Authority is inclined to approve the proposal of the CHPT.
- (iii). It is true that a corresponding change in cranage should have been done alongwith the change made in the wharfage schedule. Neither the CHPT nor the users consulted in the earlier proceeding pointed out the inter-relationship between the wharfage and cranage schedules for timber. Admittedly, this aspect has also escaped our attention.
- (iv). The understanding of the CHPT about the tariff setting process is not correct. This Authority need not wait for a Port Trusts' proposal to effect any change in the Scale of Rates. Besides Port Trusts's proposals, this Authority can decide suo motu as well as pass appropriate orders on representation from users. Before deciding the representation made by M/s. Gupta Global Exim Pvt. Ltd. about wharfage on pine-wood, the CHPT was consulted. Although it did not make any written submission, despite a reminder, the CHPT did participate in the joint hearing set up in that case. At the joint hearing, the CHPT did not indicate that it would submit a formal proposal. That being so, the case was decided based on the records available and information provided. This being the factual position, the CHPT cannot rake up an issue about deciding a case without its proposal.

- (v). The wharfage schedule for timber was amended vide this Authority's Order dated 5 November 2001. This Order was notified in the Gazette of India on 20 November 2001 and hence the amendment came into effect from that date. Since the instant proposal is for levy of an other component of handling charges and it is being approved to bring in internal consistency in the Scale of Rates, it now becomes necessary to amend the crane charges schedule, as proposed by the CHPT, with retrospective effect from the date of amendment of the relevant wharfage schedule.

5. In the result, and for the reasons given above, this Authority approves the following modification of Item No.1 (ii) (c) in Chapter III-Charges for Cranes and Fork Lift Trucks; Scale A-General of the Scale of Rates of the CHPT:

Item No.	Classification for purposes of this Scale	Rs. P.	Charge
1 (ii) (c)	Timber including pine-wood irrespective of the form in which it comes and of its endues but excluding other logs as specified in item ii (a) and (b) as above	38.60	Per Cubic metre per hoist

6. This Order will come into effect retrospectively from 20 November 2001.

S. SATHYAM, Chairman
[ADVT III/IV/143/2002/Exty.]

